राष्ट्रीय संस्करण
CopyRight - Jagran.com

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कश्मीर में संभाला मोर्चा

>> 3

वर्ष 3 अंक 58

दैनिक जागरण

मूल्य ₹6.00, नई दिल्ली, बुधवार, 7 अगस्त 2019

www.jagran.com

पृष्ठ 14

पीओके और अक्साई चिन भारत का : शाह

पक्का इरादा ▶ केंद्रीय गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा, इनके लिए लगा देंगे जान की बाजी

संसद की मुहर लगने के साथ ही आधिकारिक तौर पर खत्म हुआ अनुच्छेद 370

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को वापस लेने, अनुच्छेद 35ए को निरस्त करने और जम्मू-कश्मीर को दो भागों में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने के सरकार के प्रस्ताव पर संसद ने मंगलवार को मुहर लगा दी। यानी आधिकारिक रूप से जम्मू-कश्मीर अब भारत का अटूट हिस्सा बन गया है। इसके साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी स्पष्ट कर दिया, 'पीओके (गुलाम कश्मीर) और अक्साई चिन जम्मू-कश्मीर का हिस्सा है और उसके लिए जान दे देंगे।' उन्होंने आगे कहा, 'मैं जब-जब जम्मू-कश्मीर बोलता हूं तब-तब पीओके और अक्साई चिन इसका हिस्सा होते हैं।' अनुच्छेद 370 को जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद का मूल कारण बताते हुए शाह ने कहा कि इसके खत्म होने से लोगों को मुख्यधारा के करीब लाने में मदद मिलेगी। घाटी के लोगों से उन्होंने वादा भी किया कि उनके विकास के लिए मोदी सरकार का दिल खुला रहेगा। स्थिति सामान्य हुई तो केंद्र शासित प्रदेश को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे।

अनुच्छेद 370 व 35ए को समाप्त करने के दो प्रस्तावों और जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक पर संसद की मुहर लगते ही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं। इस पर केवल राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना बाकी है। केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी। शाह ने साफ कर दिया कि अनुच्छेद 370 के कारण सीटों के परिसीमन के रुके काम को पूरा किया जाएगा। यही नहीं, अब तक मतदान से वंचित रहे पाकिस्तान से आए शरणार्थियों और वहां रह रहे बाहरी लोगों को पहली बार विधानसभा में मतदान का अधिकार मिल जाएगा। राज्यसभा की तरह लोकसभा में भी विपक्ष में पूरी तरह बंटा हुआ दिखा। राकांपा की सुप्रिया सुले और सपा के अखिलेश यादव समेत कई सांसदों ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया और विधेयक की निंदा की। लेकिन यह नहीं बताया कि वे विधेयक के पक्ष में बोल रहे हैं या विपक्ष में। यहां तक कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसको लेकर चुटकी भी ली। टीआरएस, बीजद, बसपा जैसे विपक्षी दल लोकसभा में भी सरकार के पक्ष में खड़े दिखे तो जदयू और तृणमूल कांग्रेस ने विरोध में वॉकआउट किया। हालत यह थी विपक्ष लोकसभा में एक तिहाई का आंकड़ा भी नहीं जुटा पाया और तीन-चौथाई से अधिक सांसदों ने विधेयक का समर्थन किया।

लगभग सात घंटे तक चली चर्चा में शाह ने विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया। पूरी प्रक्रिया में कश्मीर के आम लोगों की राय नहीं लेने और फैसले को लोकतंत्र विरोधी बताने के विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए अमित शाह ने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेह, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर की जनता की आकांक्षाओं से अच्छी तरह अवगत हैं और उनकी नब्ज को समझते हैं। उसी को ध्यान में रखकर यह फैसला किया गया है।' उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद घाटी के लोग अब धीरे-धीरे मुख्यधारा के करीब आएंगे और अपनी आशाओं-आकांक्षाओं को पूरा कर सकेंगे। शाह ने विस्तार से बताया कि किस तरह अनुच्छेद 370 राज्य के विकास में रुकावट बना हुआ था। उन्होंने इसे दलित विरोधी, महिला विरोधी, जनजाति विरोधी और पर्यावरण विरोधी बताया।

विपक्ष से पूछा, अनुच्छेद 370 से क्या मिला? : शाह ने कहा विपक्ष इसके विरोध में तरह-तरह के तर्क दे रहा है, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि अनुच्छेद 370 ने किस तरह कश्मीर में विकास लाया है। उन्होंने विपक्षी सांसदों को अनुच्छेद 370 के कारण कश्मीर को हुए नुकसान पर गहराई से विचार करने को कहा। उन्होंने विपक्षी सदस्यों से पूछा, 'एक बार सोचिए तो सही कि 370 से क्या मिला। रोटी मिली, रोजगार मिला, शिक्षा मिली? अनुच्छेद 370 दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी, विकास विरोधी, महिला विरोधी है।' शाह ने विस्तार से बताया कि किस तरह संसद ने देश में विभिन्न वर्गों के कल्याण के बहुत सारे कानून पास किए, लेकिन अनुच्छेद 370 की आड़ लेते हुए उनका लाभ जम्मू-कश्मीर की आम जनता तक नहीं पहुंचने दिया गया। इसके जरिये जम्मू-कश्मीर का विकास रोका गया है।

अलगाववाद के लिए पाक ने किया अनुच्छेद 370 का इस्तेमाल : जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद के मूल में अनुच्छेद 370 को जिम्मेदार बताते हुए शाह ने बताया किस तरह 1988 में पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति ने 'ऑपरेशन टोपाक' की शुरुआत की थी। इसमें बताया गया था कि किस तरह अनुच्छेद 370 का इस्तेमाल करके जम्मू-कश्मीर के लोगों में अलगाववाद की भावना भरी जा सकती है और आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा सकता है। शाह ने कहा कि 1989 में घाटी को आतंकवाद की आग में झोंक दिया गया, जिसमें अभी तक 41 हजार से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। आखिर इन 41 हजार से अधिक लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? उन्होंने कहा कि हम हुर्रियत से बात करना नहीं चाहते, लेकिन हम कश्मीर के लोगों से बात करने के लिए तैयार हैं।

अनुच्छेद 371 रहेगा अक्षुण्ण, नगा समझौते में भी देशहित आगे : विपक्ष की ओर से जम्मू-कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा छिन जाने के बाद कई राज्यों को अनुच्छेद 371 के तहत मिले दर्जे के बारे में आशंका जताई गई। साथ ही नगालैंड में शांति के लिए एनएससीएन (मुइवा) के साथ हुए समझौते में राज्य के लिए अलग झंडा स्वीकार किए जाने की अटकलों को लेकर भी सरकार को घेरने की कोशिश की गई। लेकिन अमित शाह ने साफ कर दिया कि अनुच्छेद 371 के कारण कहीं भी अलगाववाद और आतंकवाद नहीं पनपा है इसीलिए उसे छूने का सवाल ही नहीं उठता।

फैसले का धर्म से कोई लेना-देना नहीं : अमित शाह ने सरकार के फैसले को सांप्रदायिक बताए जाने का तीखा प्रतिवाद किया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में मुस्लिम, सिख, जैन, बौद्ध और हिंदू सभी धर्मों के लोग रहते हैं और इससे सभी प्रभावित होंगे। उन्होंने 1964 में अनुच्छेद 370 पर संसद में हुई बहस का जिक्र करते हुए बताया कि किस तरह मधु लिमये से लेकर राममनोहर लोहिया तक इसके खिलाफ थे। उन्होंने विपक्ष और खासकर सपा सांसद अखिलेश यादव की ओर इशारा करते हुए पूछा कि क्या ये लोग भी धर्मनिरपेक्ष नहीं थे। उन्होंने साफ किया कि सरकार के फैसले का धर्म से कोई लेना-देना नहीं है।

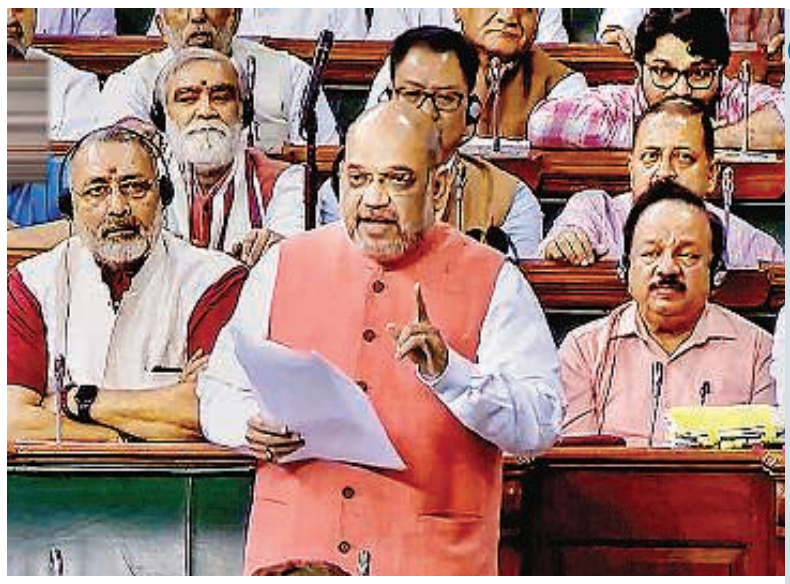

लोकसभा में मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर को विभाजित कर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के रूप में दो केंद्र शासित प्रदेश बनाने का विधेयक पेश किया। प्रेट्र

> हम एक साथ हैं, हम एक साथ उठेंगे और एक साथ मिलकर 130 करोड़ भारतीयों के सपनों को साकार करेंगे। यह हमारे संसदीय लोकतंत्र का यादगार अवसर है जहां जम्मू-कश्मीर से जुड़े ऐतिहासिक विधेयक भारी बहुमत से पारित किए गए हैं।
>
> – नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

> मुझे भरोसा है कि अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35ए के निरस्तीकरण से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोग भी नए भारत के निर्माण में हिस्सेदारी करेंगे। यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों की जीत है जो पिछले 70 साल से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे।
>
> – अमित शाह, गृह मंत्री

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख की बदली तस्वीर पेज>>5

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के राष्ट्रपति के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

नई दिल्ली, प्रेट्र : जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने संबंधी राष्ट्रपति के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई। अधिवक्ता एमएल शर्मा की ओर से दायर इस याचिका में दावा किया गया है कि राष्ट्रपति का आदेश गैरकानूनी है क्योंकि इसे राज्य विधानसभा की सहमति हासिल किए बिना जारी किया गया है। उम्मीद है कि एमएल शर्मा बुधवार को याचिका पर तत्काल सुनवाई की मांग करेंगे।

जम्मू-कश्मीर के पुनर्गठन पर '370' की मुहर

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों से पारित हो गया है, लेकिन '370' का आंकड़ा इसके नाम के साथ जुड़ा रहेगा। यह महज संयोग है कि लोकसभा ने मंगलवार को जब जम्मू-कश्मीर राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया तो उसके पक्ष में 370 मत पड़े। कई घंटे तक चली चर्चा के बाद जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विधेयक पारित करने के लिए सदन की सहमति मांगी तो कांग्रेस के एक सदस्य ने मतदान की मांग कर दी। विधेयक के पक्ष में 370 और विपक्ष में मात्र 70 मत पड़े। सदन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान के दौरान कुछ सदस्यों का मत दर्ज नहीं हुआ। उन्होंने पर्ची पर मतदान किया। इस तरह पर्ची से पड़े मतों की गणना में समय लगने से सदस्यों की जिज्ञासा बढ़ गई। जब बिरला ने मतदान का परिणाम घोषित करते हुए बताया कि विधेयक के पक्ष में 370 और विपक्ष में 70 मत पड़े हैं तो पूरे सदन में ठहाका लग गया।

सरोकार

विकास की नई बयार बहातीं डिजिटल गांवों की स्मार्ट बेटियां

पटना : गांव की पगडंडियां अब सिर्फ खेतों तक नहीं जातीं, ये कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर और बीपीओ (बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग) तक भी जाती हैं। इन कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर में बेटियां पढ़ रही हैं। नौकरी कर रही हैं। तो किसान एक क्लिक पर आयुष्मान कार्ड बनवा रहा है। ये सुनहरी तस्वीर बिहार के डिजिटल गांवों की है। (पेज-13)

जय हिंद

अभिनंदन के गांव में दोगुने उत्साह से मनेगा स्वतंत्रता दिवस

नई दिल्ली। तिरुपन्नमूर गांव से लेकर कांचीपुरम और तिरुवन्नामलाई तक, दो सौ किलोमीटर के इस पूरे बेल्ट में मानो एक अलग ही उत्साह है।

● पेज 13

ताकत वतन की हमसे है...

न्यूज गैलरी

सिटी न्यूज ▶ पृष्ठ 2

जोगाबाई एक्सटेंशन में इमारत में लगी आग, छह की मौत

नई दिल्ली : जामिया नगर थानाक्षेत्र स्थित जोगाबाई एक्सटेंशन में चार मंजिला इमारत की पार्किंग में सोमवार आधी रात आग लगने से छह लोगों की मौत हो गई जबकि चार दमकलकर्मी समेत 13 लोग घायल हो गए। बाकियों को सुरक्षित निकाल लिया गया।

राज-नीति ▶ पृष्ठ 3

निर्मोही अखाड़ा ने सुप्रीम कोर्ट में मांगी पूरी राम जन्मभूमि

नई दिल्ली : नौ वर्ष के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या राम जन्मभूमि विवाद में मंगलवार से नियमित सुनवाई शुरू हुई। निर्मोही अखाड़ा ने बहस शुरू करते हुए सुप्रीम कोर्ट से पूरी राम जन्मभूमि पर कब्जा और प्रबंधन का अधिकार मांगा।

नेशनल न्यूज ▶ पृष्ठ 6

गवाहों और पीड़िता की सुरक्षा पर कोर्ट ने मांगी सीलबंद रिपोर्ट

नई दिल्ली : उन्नाव कांड से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान मंगलवार को तीस हजारी की सत्र अदालत ने सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अदालत ने सीबीआइ से कहा है कि पीड़िता और इस केस के गवाहों की सुरक्षा व्यवस्था पर सील बंद रिपोर्ट दाखिल की जाए।

बिजनेस ▶ पृष्ठ 10

उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को मिली संसद की मंजूरी

नई दिल्ली : उपभोक्ता हितों को लेकर अरसे से लंबित उपभोक्ता संरक्षण विधेयक को मंगलवार को राज्यसभा से मंजूरी मिल गई। लोकसभा से यह पहले ही पारित हो चुका है। विधेयक में उपभोक्ताओं के अधिकारों को और मजबूती प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग का गठन किया जाएगा।

अनुच्छेद 370 पर कांग्रेस में गहराई दरार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- सिंधिया, अनिल शास्त्री, रंजीत रंजन समेत कई पार्टी नेता भी समर्थन में उतरे
- द्विवेदी, देवड़ा, हुड्डा ने पार्टी लाइन से इतर जाकर किया था समर्थन

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के मुद्दे पर कांग्रेस लगभग दो फाड़ हो गई है। पार्टी के तमाम नेताओं ने एक के बाद एक अनुच्छेद 370 हटाने के समर्थन में उतरकर कांग्रेस में इस मुद्दे पर लगभग खुले विद्रोह जैसी स्थिति पैदा कर दी है। राहुल गांधी की टीम के अहम सदस्य कांग्रेस महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अनुच्छेद 370 हटाने का खुला समर्थन किया। पार्टी की सचिव पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने भी जम्मू-कश्मीर से विवादित संवैधानिक प्रावधान हटाने का समर्थन कर दिया। जम्मू-कश्मीर पर अपने नेताओं के इस रुख से बेचैन होकर ही कांग्रेस ने संसद से प्रस्ताव पारित होने के तत्काल बाद पार्टी की आधिकारिक लाइन तय करने के लिए देर शाम कार्यसमिति की विशेष बैठक बुलाई।

राज्यसभा से अनुच्छेद 370 का संकल्प पारित होने के तत्काल बाद ही सोमवार को कांग्रेस के दिग्गज जर्नादन द्विवेदी ने इसका समर्थन कर इतिहास की गलती दुरुस्त किए जाने की बात कही थी। द्विवेदी ने पार्टी के रुख से अलग जाकर समर्थन का यह जो सिलसिला शुरू किया वह तेजी से बढ़ता हुआ मंगलवार को ज्योतिरादित्य सिंधिया और अनिल शास्त्री तक पहुंच गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रभारी कांग्रेस महासचिव सिंधिया ने ट्वीट कर कहा, 'जम्मू-कश्मीर और लद्दाख को लेकर उठाए गए कदम और भारत देश में उनके पूर्ण रूप से एकीकरण का मैं समर्थन करता हूं। संवैधानिक रूप से पूरी प्रकिया का पालन होता तो बेहतर होता। साथ ही कोई प्रश्न भी खड़े नहीं होते। लेकिन यह फैसला राष्ट्रहित में लिया गया है और मैं इसका समर्थन करता हूं।'

संसद के दोनों सदनों में पार्टी के रुख से अलग सिंधिया का जम्मू-कश्मीर के विभाजन का समर्थन करना इसलिए भी मायने रखता है कि वे लंबे समय से राहुल की टीम के अहम सदस्य रहे हैं। सिंधिया से पहले राहुल बिग्रेड के सदस्य पूर्व सांसद दीपेंद्र हुड्डा और मिलिंद देवड़ा जैसे कांग्रेस के युवा नेताओं ने अनुच्छेद 370 हटाने के ऐतिहासिक फैसले का खुला समर्थन किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी लाइन से इतर नेताओं के इस सुर पर नाराजगी भी जताई मगर बात नहीं बनी। बिहार की पूर्व सांसद रंजीत रंजन ने भी जम्मू-कश्मीर पर सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि इस बात की खुशी है कि सरकार अनुच्छेद 370 को खत्म कर रही है और इसकी वजह से कश्मीरी पंडितों को काफी दर्द झेलना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की मुखर विधायक अदिति सिंह ने भी अपने अंदाज में सरकार के कदम का समर्थन किया।

कांग्रेस के एक और नेता अनिल शास्त्री ने पार्टी नेतृत्व को देश की जनभावना भांप इसके अनुरूप अहम मसलों पर दृष्टिकोण तय करने की सीख दी। शास्त्री ने कहा कि इस मामले पर जनता पूरी तरह सरकार के साथ है। कांग्रेस नेता ने पार्टी नेतृत्व को आगाह किया कि मंडल का विरोध करने की वजह से उत्तरप्रदेश और बिहार में हम हार गए। इसीलिए पूरा भारत हाथ से निकल जाए इसका जोखिम नहीं लेना चाहिए।

अधीर की 'अधीरता' से कांग्रेस की किरकिरी, सोनिया नाराज

नई दिल्ली : लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी की भाषण शैली की कमजोरी बड़े मौकों पर कांग्रेस की किरकिरी करा रही है। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने पर चर्चा शुरू होने से पहले अधीर ने गृह मंत्री अमित शाह से अटपटे सवाल कर उन्हें कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करने का मौका दे दिया। सरकार को घेरने में अधीर के इस अधीरता से पार्टी की हुई किरकिरी ने पार्टी संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी को सदन में ही असहज कर दिया। सोनिया गांधी ने इसको लेकर अधीर से नाराजगी भी जाहिर की और उन्हें सदन में कांग्रेस की आधिकारिक लाइन के अनुरूप तैयारी कर बोलने की नसीहत भी दी। (पेज-4)

नेहरू-पटेल की भूमिका पर लोकसभा में तीखी तकरार

नई दिल्ली : भारत के एकीकरण में जवाहर लाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका को लेकर कांग्रेस और भाजपा में चलती रही जंग एक बार फिर सामने आ गई। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के प्रस्ताव पर लोकसभा में हुई पूरी चर्चा में नेहरू-पटेल की भूमिका को लेकर पक्ष और विपक्ष में तीखी तकरार हुई। भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने जम्मू-कश्मीर के भारत में पूरी तरह से विलय न होने का जिम्मेदार नेहरू को ठहराया तो कांग्रेस की ओर से जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि हैदराबाद और जूनागढ़ की रियासतों को भी भारत का हिस्सा बनाए जाने का श्रेय दिया गया। (पेज-4)

नहीं रहीं पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली

- दिल का दौरा पड़ने से हुआ निधन, आज होगा अंतिम संस्कार
- पीएम मोदी ने ट्वीट किया, 'भारतीय राजनीति के एक गौरवशाली अध्याय का अंत'

पूर्व विदेश मंत्री और भाजपा की कद्दावर नेता सुषमा स्वराज का मंगलवार देर रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 67 वर्ष की थीं। सुषमा स्वराज के परिवार में उनके पति स्वराज कौशल और उनकी बेटी बांसुरी हैं।

एम्स सूत्रों ने बताया कि सुषमा को रात करीब 9.35 बजे सीधे एम्स के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया था, लेकिन करीब 11 बजे उनका निधन हो गया। इमरजेंसी में भर्ती होने के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, प्रकाश जावड़ेकर और नितिन गडकरी उन्हें देखने पहुंचे थे। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया कि बुधवार सुबह 11 बजे तक सुषमा का पार्थिव शरीर उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक उनका पार्थिव शरीर कार्यकर्ताओं और लोगों के अंतिम दर्शनों के लिए पार्टी मुख्यालय में रखा जाएगा। दोपहर 3 बजे से उनकी अंतिम यात्रा निकलेगी और लोधी रोड स्थित शवदाह गृह में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुषमा के निधन पर ट्वीट कर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा, 'भारतीय राजनीति के एक गौरवशाली अध्याय का अंत हो गया है। भारत एक असाधारण नेता के निधन से शोकाकुल है जिसने अपना जीवन लोगों की सेवा और गरीबों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए समर्पित कर दिया। सुषमा जी अपने तरह की अकेली थीं जो करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत थीं।' मोदी ने लिखा कि सभी दलों में उनके प्रशंसक थे।

उनके निधन के साथ एक विडंबना यह रही कि कुछ घंटों पहले ही उन्होंने ट्वीट कर मंगलवार को अपने जीवन का सबसे अच्छा दिन बताया था। एक अन्य विडंबना यह भी है कि दिल्ली ने एक माह के भीतर दो पूर्व महिला मुख्यमंत्रियों को गंवा दिया है। ध्यान रहे कि 20 जुलाई को शीला दीक्षित का निधन हो गया था। सुषमा स्वराज ने स्वास्थ्य कारणों के चलते ही इस साल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया था। उन्होंने अप्रैल 2016 में एम्स में ही किडनी ट्रांसप्लांट कराया था। उन्हें किसी पार्टी की पहली महिला प्रवक्ता, पहली युवा महिला सांसद, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री और पहली महिला विदेश मंत्री होने का गौरव हासिल था।

14-02-1952 से 06-08-2019

आखिरी ट्वीट

'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, धन्यवाद। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं अपने पूरे जीवनकाल में इस दिन का इंतजार कर रही थी।' (तबियत बिगड़ने से कुछ घंटे पहले जम्मू-कश्मीर मामले पर केंद्र सरकार को बधाई दी थी।)

दरियादिल स्वभाव वाली दक्ष नेता

नई दिल्ली : सुषमा स्वराज की पहचान प्रखर वक्ता और कुशल राजनेता के साथ एक संवेदनशील राजनीतिक हस्ती की भी थी। इसी कारण उनकी सराहना विरोधी दल के नेता और यहां तक कि भाजपा के कट्टर आलोचक भी करते थे। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में बतौर विदेश मंत्री उन्होंने देश के साथ विदेश में भी छाप छोड़ी। वह पाकिस्तान में भी एक सहृदय नेता के तौर पर जानी जाती थीं। तनावभरे संबंधों के बावजूद वह वहां के बीमार लोगों को भारत का वीजा देने में उदारता बरतती थीं। इसके चलते ट्विटर पर वीजा मांगने वाले पाकिस्तानियों की कतार लगी रहती थी। कई लोगों को वह खुद ट्विटर के जरिये सूचित करती थीं कि आपका वीजा स्वीकृत हो गया है। (पेज-6)

गहराता संकट

कांग्रेस के पास भूल सुधार का मौका था, लेकिन वह चूक गई, मोदी-शाह ने एक झटके में न सिर्फ पार्टी के एजेंडे, बल्कि देश की तमन्ना को परवान चढ़ा दिया

जनभावना को समझने में फिर चूकी कांग्रेस

त्वरित टिप्पणी

प्रशांत मिश्र

कश्मीर को अनुच्छेद-370 से आजादी मिल गई, जम्मू-कश्मीर भारत का अटूट अंग बन गया। देश में और संसद में जो माहौल है उसमें यह तो होना ही था। आश्चर्य यह है कि देश की इस तमन्ना को समझने और उसे पूरा करने के लिए साहसिक कदम उठाने में आखिर 70 साल कैसे लग गए। लेकिन फिलहाल सवाल यह है कि कांग्रेस समेत जो लोग और दल इसका विरोध करते रहे वह देश की भावना के विपरीत क्यों चल रहे हैं। कांग्रेस आखिर कब हकीकत से रूबरू होगी? कब समझेगी कि वह खुद ही अपने हाथ जला रही है? कब अहसास होगा कि उसकी राजनीतिक सोच जनमानस की सोच से परे है? पहले ही हाशिये पर खड़ी कांग्रेस के नेतृत्व के लिए जम्मू-कश्मीर पर चर्चा के वक्त भूल सुधार का एक मौका था, लेकिन वह फिर चूक गई।

अभी बहुत दिन नहीं गुजरे हैं जब लोकसभा में करारी हार के बाद राहुल गांधी ने बहुत ही गैर जवाबदेह तरीके से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। वह अप्रत्यक्ष रूप से हार का ठीकरा दूसरे नेताओं के सिर फोड़ रहे थे। आखिर तक उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया कि खराब प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण वह खुद रहे थे। जिस तरह उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईमानदारी पर सवाल खड़ा किया था वह जनमानस को अच्छा नहीं लगा था। उससे पहले के चुनावों में जिस तरह सेना के पराक्रम पर सवाल खड़ा किया था और कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता सवाल खड़े कर रहे थे, वह जनमानस को अच्छा नहीं लगा था। खुद कांग्रेस के अंदर ही पार्टी के रुख को लेकर उसी तरह सवाल उठ रहे थे जैसे जम्मू-कश्मीर को लेकर पार्टी के अंदर मतभेद दिखा। लेकिन समझ नहीं आता है कि आखिर कांग्रेस नेतृत्व को हो क्या गया है। आंखें बंद हो गई हैं या कान पर हाथ रख लिया है।

जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 के अस्थायी विशेष प्रावधान को हटाने का मौका आया तो ऐन वक्त पर कांग्रेस के अंदर दरार दिखने लगी। नेतृत्व ने तय किया कि प्रक्रिया को आधार बनाकर विरोध तो करेंगे ही। क्या कांग्रेस को इसका अहसास नहीं है कि अनुच्छेद-370 कैसे अब तक राज्य के विकास के लिए बाधक बना रहा। कई केंद्रीय योजनाएं पूरे देश में चल रही हैं लेकिन जम्मू-कश्मीर में वह लागू नहीं है। अनुच्छेद-370 कैसे राज्य के विकास में बाधक बना है इसके कई आंकड़े स्वयं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने गिनाए, लेकिन विरोध करने वाले 370 के उपयोग का एक तर्क भी नहीं गिना पाए। कांग्रेस की ओर से भी कोई ऐसा तर्क नहीं आया। फिर विरोध किस बात का और अगर राजनीति की खातिर ही कांग्रेस इसका विरोध कर रही है तो लाभ क्या मिलने वाला है। सच्चाई तो यह है कि इस अहम मुद्दे पर बसपा, अन्नाद्रमुक जैसी पार्टी जनता के मन को समझ गईं लेकिन कांग्रेस फिसल गई।

दूसरी ओर पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने वह कर दिखाया है जिसकी चाह देश के मन में वर्षों से थी। पूरी तैयारी के साथ पहले जनभावना समझी, स्थानीय लोगों की परेशानी को परखा, चौतरफा पेशबंदी की और फिर कानून सम्मत तरीके से इतिहास की एक बड़ी गांठ को खोल दिया। एक झटके में न सिर्फ पार्टी के एजेंडे और देश की तमन्ना को परवान चढ़ा दिया बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी मजबूत सरकार का एक संदेश दे दिया है। यह सच है कि कांग्रेस और भाजपा की दूरी बहुत बढ़ गई है लेकिन अगर कांग्रेस इसे पाटने का सपना भी देखती है तो पहले सोच दुरुस्त करनी होगी।

कश्मीर में हो सकते हैं पुलवामा जैसे हमले : इमरान

- कहा, भारत-पाक में युद्ध का कारण बन सकता है मोदी सरकार का फैसला
- बाजवा ने कहा, कश्मीरियों की मदद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं

इस्लामाबाद, प्रेट्र : जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने के मोदी सरकार के फैसले से पाकिस्तान बुरी तरह बौखला गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने तो भारत को धमकी देते हुए कहा है कि इस फैसले के बाद पुलवामा जैसे हमले हो सकते हैं, जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के कारण बन सकते हैं। मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान भारत स्थिति अपने कार्यवाहक उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह को वापस बुलाने पर भी विचार कर रहा है। भारत के लिए पाक के नामित उच्चायुक्त मोइन-उल-हक अभी अपने देश में ही हैं और उनके 16 अगस्त को कार्यभार संभालने की उम्मीद है।

कश्मीर मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाए गए पाक संसद के संयुक्त सत्र में इमरान खान ने चेतावनी देते हुए कहा, 'यह ऐसा युद्ध होगा जिसमें जीत किसी की भी नहीं होगी और उसका प्रभाव वैश्विक होगा।' परमाणु क्षमता वाले पड़ोसियों के बीच युद्ध छिड़ने के हालात को बताते हुए इमरान खान ने कहा, 'कश्मीरी विरोध प्रदर्शन करेंगे और भारत उन्हें दबाएगा। ऐसे में फिर पुलवामा जैसे हमले होने तय हैं। मैं पहले ही यह अनुमान लगा सकता हूं कि यह होगा। भारत इसके लिए फिर हमें दोषी ठहराने की कोशिश करेगा। वह हम पर हमला कर सकता है और हम उसका जवाब देंगे। इसके बाद क्या होगा?...वह युद्ध कौन जीतेगा? कोई भी इसे नहीं जीतेगा और पूरी दुनिया के लिए इसका परिणाम भयावह होगा। यह न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं है।'

अंतरराष्ट्रीय समुदाय से कश्मीर मुद्दे का संज्ञान लेने की गुहार लगाते हुए इमरान खान ने कहा, 'उन्होंने जो भी कश्मीर में किया वो अपनी विचारधारा के मुताबिक किया...उनकी नस्लीय विचारधारा है।' प्रधानमंत्री खान ने कहा कि पाकिस्तान हर मंच पर भारत के फैसले के खिलाफ लड़ेगा। भारत के फैसले के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय अदालत और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जाने पर भी विचार किया जा रहा है।

इससे पहले, संसदीय कार्य मंत्री आजम खान स्वाति ने प्रस्ताव पेश किया, जिसमें नियंत्रण रेखा के उल्लंघन के लिए भारत की निंदा की गई थी, लेकिन अनुच्छेद 370 को खत्म करने का जिक्र नहीं था। इससे विपक्षी दल भड़क गए और संयुक्त सत्र के बहिष्कार की धमकी दे डाली। इस पर नेशनल असेंबली के स्पीकर असद कैसर ने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी।

पाक सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर कमांडरों के सम्मेलन में कहा कि सेना किसी भी हद तक जाकर कश्मीरियों की मदद करने के लिए तैयार है। पाक सेना कश्मीरियों के संघर्ष में उनके साथ खड़ी है। पाक सेना ने एक बयान में कहा कि भारत ने जिस अनुच्छेद 370 और 35ए को खुद खारिज कर दिया है, उसे पाकिस्तान ने कभी स्वीकार ही नहीं किया था।

इमरान खान फाइल फोटो